शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका
राष्ट्रीय छात्रशक्ति

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 4 ■ अंक 01 ■ नवम्बर 2020 ■ ₹ 10 ■ पृष्ठ 36

34 साल बाद देश को मिली राष्ट्रीय शिक्षा नीति

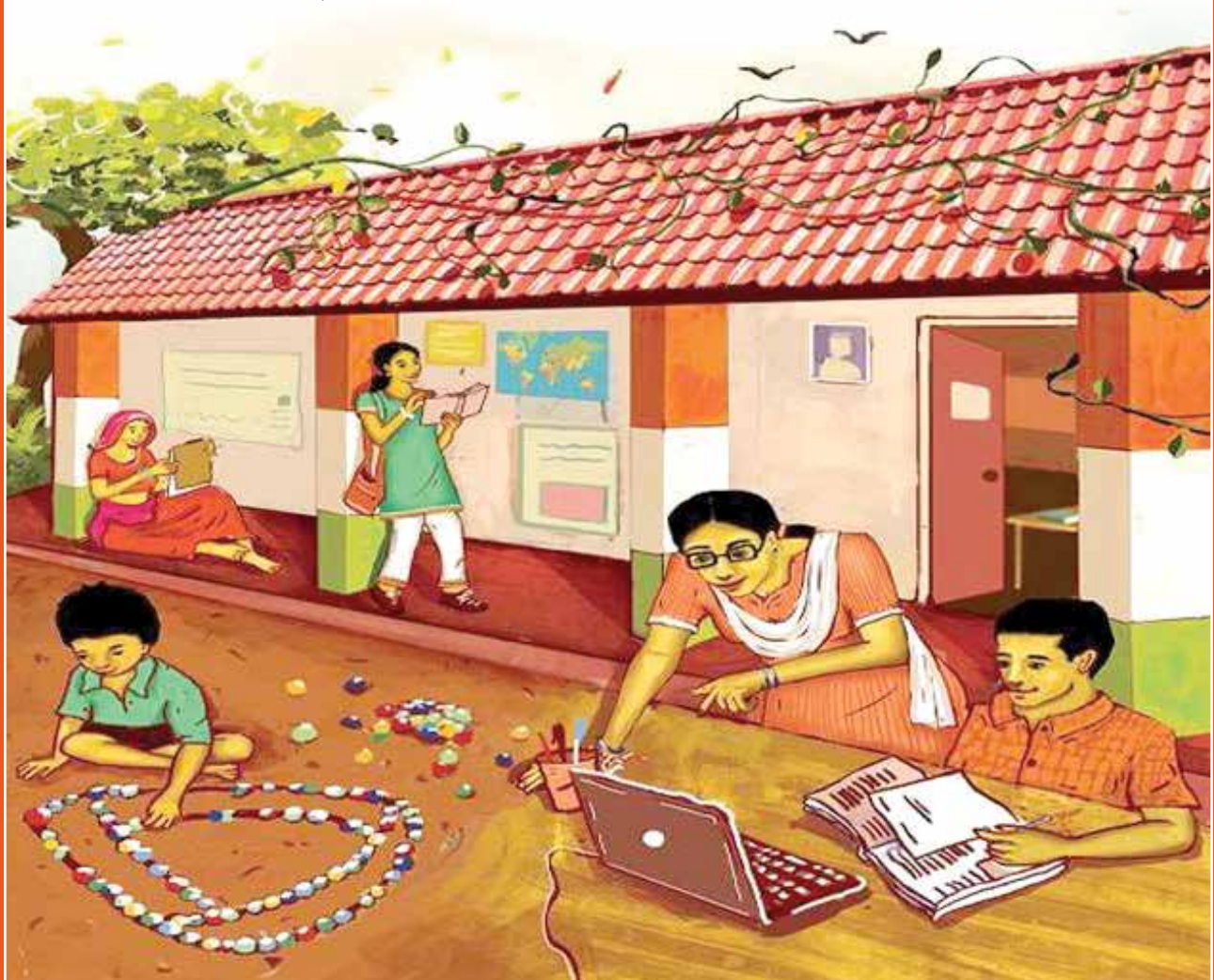

परिषद गतिविधियां

शिष्टाचार भेंट के दौरान खेल मंत्री किरेन रिजिजू (मध्य में) के साथ (बाएं से) अभाविप दिल्ली प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव पर्वतारोही शोभित शर्मा, सौरभ किट्टू टांक एवं मेघा परमार

कानपुर : स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान यमुना नदी में फैले गंदगी का सफाई करते विकासार्थ विद्यार्थी कार्यकर्ता

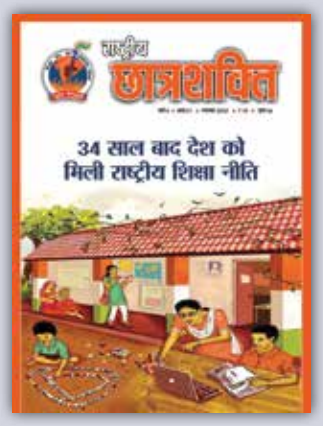

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 4, अंक 01
नवम्बर, 2020

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रीत।

इस अंक में

05 DECODING NATIONAL EDUCATION POLICY 2020

Education is the single greatest tool for transforming an individual and society with...

संपादकीय	04
नई शिक्षा नीति से स्कूली शिक्षा में आएंगे बुनियादी बदलाव	11
UNDERSTANDING THE NATIONAL EDUCATION POLICY (NEP)	15
अभाविप की ऑनलाइन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक इंदौर में संपन्न	17
STRICT ACTION AGAINST THE PROPRIETORS OF FAKE UNIVERSITIES REQUIRED : ABVP	19
अभाविप प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय राज्यमंत्री कैलाश चौधरी को सौंपा ज्ञापन, कृषि शोध से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग	20
अभाविप की अनूठी पहल 'परिषद की पाठशाला'	21
NEW EDUCATION POLICY: A VISION FOR HOLISTIC DEVELOPMENT THROUGH VOCATIONAL AND HIGHER EDUCATION	23
पटना : शैक्षिक,सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन के संकल्प साथ संपन्न हुआ विश्वविद्यालय छात्र नेता सम्मेलन	26
नशाखोरी परिसर संस्कृति को भंग करने वाली, देश भर में हो नशे पर व्यापक बहस : अभाविप	27
अभाविप के नेतृत्व में खेल मंत्री से मिला पर्वतारोहियों का प्रतिनिधिमंडल	28
RECENT FARM BILLS 2020 – ENSURING SUSTAINABILITY AND PROFITABILITY OF FARMING COMMUNITY	29
हैदराबाद : अभाविप की तेलंगाना सरकार से मांग, आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के लिए दस प्रतिशत आरक्षण कोटा लागू करे	31
INDIA'S DIPLOMATIC AND STRATEGIC TOOLS: POLITICAL WEAPONS IN THE INDIA–CHINA STANDOFF	32

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

वर्ष 2020 की शुरुआत ही आशंका के साथ हुई। विश्व के अनेक देश कोरोना के साये में आ चुके थे और भारत पर भी उसका खतरा मंडरा रहा था। केन्द्र सरकार ने सुरक्षात्मक पहल करते हुए लॉकडाउन किया तो उम्मीद थी कि तीन सप्ताह बाद यह खतरा काफी कम हो चुका होगा। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। रोग बढ़ता गया ज्यों–ज्यों दवा की।

सही समय पर सही निर्णय लेकर भारत ने लाखों जीवन बचा लिये। यदि लॉकडाउन की श्रंखला न लागू की गयी होती तो शायद स्थिति इससे बहुत अधिक भयावह होती। कुछ महीनों के लिये देश में सब कुछ ठहर सा गया। साथ ही ठहर गयी आपकी प्रिय पत्रिका 'छात्रशक्ति' भी। छापाखाने भी बंद थे और डाक व्यवस्था भी। न प्रकाशन संभव था और न ही वितरण। ऐसे में कुछ समय के लिये 'छात्रशक्ति' का प्रकाशन रोकना अनिवार्य हो गया था।

पत्रिका रूप में 'छात्रशक्ति' के अभाव को ऑनलाइन सामग्री द्वारा पूरा करने के किंचित प्रयास किये गये। 'छात्रशक्ति' की वेबसाइट पर अद्यतन समाचार और आलेख देकर जिज्ञासा समाधान के प्रयास भी हुए किन्तु अभ्यस्त आंखें इसे पत्रिका के कलेवर में देखना चाहती हैं, यह भी निश्चित ही है।

वैश्विक महामारी के इस दौर में भी दुनिया के अनेक देशों में आतंक का कहर बरसा। फ्रांस और ऑस्ट्रिया इसके उदाहरण हैं। कोरोना की दूसरी लहर और एक बार फिर लॉकडाउन के शिकंजे में फंसी दुनिया को चौपट होती अर्थव्यवस्था के बीच हिंसक प्रवृत्तियों सं खुद को बचाने की दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है।

भारत में पहले से जारी शाहीन बाग और उसके बाद देश की विभाजनकारी शक्तियों ने साम्प्रदायिक और जातिगत विद्वेष की खाई को और चौड़ा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। आज भी यह जारी है। विडम्बना है कि दलगत लाभ के लिये राजनैतिक दलों ने भी इन शक्तियों के साथ गठजोड़ कर लिया है जो देश में सदभाव के लिये बड़ी चुनौती है।

यह संतोष का विषय है कि कोविड 19 पर समय रहते प्रभावी नियंत्रण और देश के नागरिकों द्वारा कठिनाइयों के बावजूद इस संकट की घड़ी में नेतृत्व के प्रति व्यक्त किये गये विश्वास ने भारत को इससे उबरने और आगे बढ़ने का हौंसला दिया है। हमेशा की तरह, विपरीत परिस्थिति को मात देकर भारत एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। विकास की यात्रा पर बढ़ चला है। सभी क्षेत्रों में गतिविधियां शुरू हो गयी हैं।

परिषद भी सदैव की भांति चुनौती के इस संकट के समय में अपने सेवाकार्य द्वारा तथा बस्तियों में स्कूली बच्चों की शिक्षा द्वारा अपनी भूमिका निर्वाह करती रही। अगले चरण के रूप में, पुरानी भूमिका को फिर से प्रारंभ करने के निश्चय के प्रतिफल के रूप में छात्रशक्ति का यह अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है।

दीपावली की हार्दिक शुभकामना सहित,

आपका
संपादक

DECODING NATIONAL EDUCATION POLICY 2020

| Milind Marathe |

Education is the single greatest tool for transforming an individual and society with achieving social justice and equality. Education offers equal opportunity to every citizen to dream, thrive and contribute to the nation. Acquiring knowledge, wisdom and continuous search for ultimate "Truth" is the objective of education. It leads to self-realization and liberation.

"sa vidya ya vimuktaye" means Knowledge that only liberates. Body should be liberated from laziness, idleness, mind should be liberated from fluctuations, instability and Intellect should be liberated from inertia and slavery of mind. That is the objective of education and education policy should lead towards this goal.

What great people said about Education ?

Swami Vivekanand :- " Education is not the amount of information that we put in to your brain and runs riot there, undigested , all your life but we must have life-building, man-making, character–building education. It should unite Head, Heart and Hand through Education."

Yogi Arabindo:- "Today's crisis is the crisis of Character & until we effect fundamental chages in the objectives of education, subjects, it's system, Bharat can not be re-constructed."

Mahatma Gandhi from "NayeeTalim" depicts 5 principles of education

1. All round Development:- "Main aim of education should be to draw the best out of a person's mind, body and

soul. This is to say that he must not only develop at the mental level but also at physical, spiritual, aesthetic and intellectual level. The aim should not just be to provide literacy but to develop the students in every aspect."

2. Mother Tongue as the Medium of Instructions.

3. Social Awareness and Service:- Socially awareness, love for motherland & to live in coordination with their fellow citizens and help must be taught from the very beginning.

4. Education of the Heart:-Purity of Heart Indispensable. Purity of personal life is the one indispensable condition for building a sound education.I do not believe that this can be imparted through books. It can only be done through the living touch of the teacher.

5. Craft Centred Education: - Handicraft is the means to develop the mind as well as soul. Thus, schools must not focus on theoretical knowledge. They must instead introduce craft from the pre-primary classes. This would help in invoking creativity, innovation and also enhance the mind-hand coordination.

ABVP is of the opinion that National Education Policy 2020 has expressed great resolve to bring the ideas of these Great personalities in to reality.

Background of NEP 2020 :

After 1986 New Education Policy, 34 years have passed. Student's number aspiring for education has increased leaps and bound. Desire to get educated is increased and now it's very high across the cast,religions ,rich and poor, urban and rural population.

Technology has changed and Industry 4.0 revolution is knocking the doors. Employment avenues, businesses and business models are changing fast. Mobile phone, Computer and Internet penetration is ever increasing.So every student will need 21st century Qualities like deep knowledge in 1 or 2 core subjects , good knowledge of multi-disciplinary subjects like arts, languages, social science, economics, high Computer Literacy, fast capability to learn new things, adapt, assimilate and deliver solutions in new environment, structured thinking, excellent communication and inter-personal working capabilities, creativity, innovations, intellectual curiosity , Bharatiya value systems, ethical compass, character and service attitude. This policy has taken note of these challenges and drafted.

"NEP 2020 envisions an India centric education system there by transforming India sustainably in to an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all."

ABVP welcomes the policy whole heartedly and decodes its important, brilliant features.

1. ECCE AND SCHOOL EDUCATION STRUCTURE:-

Revolutionary re-structuring of school curriculum is made in from present 10 + 2 school structure to 5+3+3+4 design and it is named as "Early Childhood Care and Education (ECCE).

Neuroscience shows that 85% of Child's Cumulative Brain Development occurs from 0 to 6 years and thus learning process for a child starts immediately after birth. Various levels of neglect and deprivation in early childhood is the root cause of deficiencies in development of critical areas of brain.So excellent care, nutrition, physical and emotional hand-holding, nurture is a must for all children. In Bharat almost all urban poor, rural children don't get this support. NEP 2020 included education of this age group, 4 to 6 years for the first time formally under Ministry of Education and ensured that no child will lag due to neglect and deprivation. It is a very welcoming step.

Foundational stage from age 3 to 8 comprises of pre-primary school of 3 years and grade 1 and 2 . It will have flexible, play-based, activity based, discovery based learning.Preparatory stage from age 8 to 11 is of 3 years and grade 3rd, 4th and 5th will comprise of reading, writing, speaking, language, art, science, mathematics, sports and physical education. Every student in grade 5 and beyond will achieve foundational literacy and numeracy. It is considered as an urgent National Mission. Middle stage from age 11 to 14 is of 3 years and grades 6th,7th and 8th will comprise of more formal style of learning with social science, humanities, deeper and experiential learning of subjects. High stage is of age 14 to 18 of 4 years and grades 9th , 10th, 11th and 12th . It will be now multi-disciplinary study, vocational subjects, skill- based courses with great depth, greater critical thinking, more flexibility with student's choice.

All stages mentioned above will heavily incorporate local traditions, ethical reasoning and digital literacy, creative, collaborative and exploratory activities. This will move the school education system towards learning how to learn, increased flexibility in choice of subjects.

NEP 2020 has suggested that there will be no hard separation in terms of curricular, extra-curricular and co-curricular. No hard separation of Vocational or skill based streams and academic streams. So everything is equally important and equally curricular. So no stream, subject will be looked down and inferior to any other one. In line with the schooling age, RTE is extended up to 18 years in NEP 2020.

U-DISE data of 2016-17 shows 28 % of public primary and 14.8 % of upper primary schools have less than 30 students and even less.119303 single-teacher schools are working. This shows that we have not yet touched to quality aspect of schools.Due to small size of school it's very difficult or next to impossible to allocate good human resources like expert teachers, counsellors, music teacher, computer lab instructor and physical resources like laboratory equipment, library books, facilities for sports, music and arts activities. Governance and management become difficult with small size and vibrancy is lost.It starts functioning sub-optimally. Thus NEP 2020 has come up with very good and workable idea of School Complex.Nearby schools will be organized in to School Complexes and will be treated as a basic entity for governance under the signed MoU.It will enable to share key physical resources as well as human resources mentioned above. This complex can integrate ECCE, vocational education, needs of special children also. It's a complete revamping of school education and ABVP welcomes it.

2. EDUCATION IN THE LOCAL LANGUAGE OR MOTHERTONGUE

Language is not only the medium of instruction but it is theexpression of an Individual, of a society and its collective continuity in culture. It is also proved that clarity of fundamentals, abstract thinking, innovation comes if a child is taught in mother toung. So NEP 2020 strongly suggests that the medium of instruction preferably till grade 8th or at least till grade 5th will be the home language/mother tongue/local language. Continuation of present three language formula in its spirit to make students capable in communicating in multiple languages with required flexibility.

3. SPECIAL CARE FOR INCLUSION OF THE LESS FORTUNATE PEOPLE:-

Even after 73 years of independence education is not reached to all children of

Bharat. There are many Socio Economic Disadvantaged Groups (SEDGs) which are still out of education and special care and inclusion of them is a pre-requisite of developed Bharat. SEDGs in education are categorized by NEP 2020 in to those having given gender identities like women and transgender individuals.Socio-cultural identities like SC, ST, OBCs, Muslims, migrant communities.Special needs like learning difficulties & Differently abled students.Socio-economic identities like urban poor, rural needy and migrant labours.

NEP 2020 is very sensitive towards this issue and has come up with various measures to attain full equity and inclusion. Various solutions should be identified sensibly on case to case basis. Gender inclusion fund, targeted scholarships and other financial support, monetary incentives to parents, bicycle provision for girls, declaring large population regions of certain SEDGs as Special Education Zones are some of the measures suggested by NEP 2020.

Availability and capacity development of teachers, reducing pupil- teacher ratio to 25:1 and very importantly to change the culture of schools to make them free from discrimination, harassment, intimidation and make them sensitize about the needs of SEDGs is the resolve of NEP 2020.

4. RESTRUCTURING AND CONSOLIDATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (HEI):-

India has over 800 Universities and40000 + colleges.Over 40% of all these colleges run Only Single Programme. Over 20 % of colleges have enrolment below 100, while only 4 % of colleges have enrolment over3000 (AISHE Report 2016-17). This fragmentation leads to sub-optimal performance with small size.Rigid boundaries of disciplines and fields, lack of research at most of the Universities and colleges leading to lack of research culture in HEIs ,lack of teachers and Institutional Autonomy and lack of employability are the challenges faced by Higher Education in India. After independence Indian HE system was predominantly affiliating type of system. But in last 70 years we could not get desired results. So let us say good bye to affiliating system and make all our HEIs either Research or Teaching Universities or degree granting autonomous colleges.

So NEP 2020 has suggested brilliant idea of establishing large multi-disciplinary universities and colleges with teaching programs across the disciplines and fields. End of fragmentation of HE and wide flexibility to students to choose subjects across the disciplines will be the unique feature of HE. All present universities and colleges will have to decide,whether they will become Research Intensive Universities, Teaching Intensive Universities and Autonomous Colleges depending on their strengths, willingness and capabilities. They will have autonomy and freedom to move from one type to another type.

Multiple exit option is also very useful for students. It will acknowledge each year's effort and will award certificate after completion of 1 year, Diploma after 2 years, Degree after 3 years and Holistic Degree after 4 years.

Academic Bank of Credits is also a commendable idea floated by NEP2020, which will enable students to acquire credits from different institutes at different years and get degree once required credits are earned.

15 to 20 % credits can be earned through MOOCs in ICT mode.

5. SHIFTING TOWARDS EDUCATION OF HEAD, HEART AND

HAND OR HOLISTIC EDUCATION:-

Holistic education is the need of an hour. In modern terminology its education of Cognitive domain, Affirmative domain and Psychomotor domain. Balance of these three domains must be re-established.

This critical ancient Bharatiya concept ofbalanced educationor Holistic Education is brought back by NEP 2020. It is integration of STEM(Science, Technology,Engineering, Mathematics) with humanities and arts.Medicine and physics, aeronautical engineering and Sanskrit.Holistic education is innovation and critical thinking, higher order thinking,inter-personalrelations,working in a team, communication of all types, problem solving approach, foundation of social work, understanding feelings of self and others, internships and research opportunities, developingconstitutional values, ethical values, understandingidea of Bharat, training of concentration of mind and detachment of mind, learning by doing and many more. It is interwoven in under graduate course by making a 4 year bachelor program of holistic education. There will be multiple exit option in 4 years Graduation course for students. The whole idea is students willnot be only prepared for the LESSONS but for LIFE.

6. DEVELOPING RESEARCH CULTURE AND MIND-SET THROUGH NRF:-

NEP 2020 is committed to develop vibrant knowledge society. Innovation, new ideas, creation of new knowledge, new products, new systems, new processes depending on requirements of Bharat, filing patents will lead to creation of wealth. That will make "Aatm-nirbhar Bharat". But for that serious research culture and mind-set should be developed in education. Establishment of National Research Foundation (NRF) is another revolutionary, most needed feature of NEP 2020.

NRF will stimulate and expand research in India. It will seed, cultivate and grow research culture right from schools to HEIs. It will monitor, mentor the HEIs by eminent research scholars across the countryand link Universities and National Research Laboratories (NRL).

NRF will fund competitive, peer-reviewed grant proposals of all types and of all disciplines. It will act as an umbrella organization between researchers, HEIs, funding departments of government, Industries, NRL and policy makers and synchronize the efforts for research.

7. NO TO COMMERCIALISATION OF EDUCATION:-

In last few years cost of education per student per year is escalating and is going out of the reach of common students. Commercialization of education is very much seen and ABVP is fighting against commercialisation. NEP 2020 clearly proclaims that Education is a not-for-profit activity. It is a charitable activity and commercialization of education is not at all acceptable.Actually affordable and quality education is the need of an hour.

Public expenditure on education in India was 2.7 % of GDP in 2017-18 which was around 10 % of total government (centre and state) spending.NEP 2020 categorically said that there is need of significant increase in public investment from current 10 % of overall investment to 20 % in a next few years. It recommends 6 % of GDP should be invested for education.

8. NEW GOVERNANCE STRUCTURE:-

Higher Education will be governed by 4 pillars namely Regulatory Council for

general administration and regulation, National Accreditation and Assessment Council for quality checks of all Institutes, Standard Setting Council for prescribing bench marks for quality and National Grants Council for funding. It is separate but synchronised system to carry out various tasks effectively.

9. Teachers are on the fore front:-

Spirit of NEP 2020 is Teachers. Teachers are on the forefront of this policy. All revolutionary measures will be implemented in letter and spirit only with the dedicated participation of teachers. Teachers will impart knowledge, skills and right attitude in students. They will only imbibe moral values, life skills in the students. So we need passionate, motivated, highly qualified, professionally trained, well equipped teachers with mother like heart for their students at all levels of education.

NEP 2020 proposed teacher education of 4 year integrated B.Ed. program after 12th standard, 2 years after graduation and 1 year after post- graduation with subject knowledge, pedagogy and educational technology expertise, students psychology. Special merit scholarship coupled with guaranteed employment in rural areas for brilliant students as a teacher. NEP 2020 has given clear direction to fill all the vacant posts of teachers with rigorous, impartial, transparent process. All Para-teacher system across the country will be stopped by 2022 and closure of substandard teacher education institutes will be done on top priority.

Continuous in service training, creating inclusive, effective and protective academic atmosphere and excellent work culture for teachers is given top priority in NEP 2020.

NEP 2020 is an India centric, Indian education system with indigenous wisdom and roots alongwith primacy of Indian languages.It is students' friendly, integrated, inclusive, comprehensive,and holisticand forward looking. It has a capacity to completely revamp the colonial education system and mind-set.

ABVP is of the opinion that now steps to implement NEP2020 has to be taken fast. Time is slipping and nothing concrete has been done particularly in Higher Education for implementation. UGC has formed some committees for implementation but ABVP feels that UGC is already over-burdened and perhaps cannot implement it in its full totality. So ABVP demands to Central Government to form National Task Force (NTF), supported by members of re-drafting committee, at the apex with full mandate to guide, act and monitor the implementation. Members of NTF should be of very high calibre and integrity, eminent and visionary personalities from different walks of life.

Central Universities, some State Universities, Institutes of eminence, well-meaned private institutes and industries should start working on implementation of various ideas of NEP 2020.

Re-orientation of lower cadres in education, selected teachers, managements of schools and colleges, NGOs in education sector and officials of Universities is needed. Webinars on how to implement NEP 2020 for small, specific and focused areas should be arranged and road map must be prepared.

ABVP appeal to all the members of education fraternity, including government, to come forward and take maximum efforts for successful implementation of this game changer NEP 2020. ■

नई शिक्षा नीति से स्कूली शिक्षा में आएंगे बुनियादी बदलाव

| अभिषेक रंजन |

नई शिक्षा नीति के बारे में आप क्या कहेंगे? ये सवाल सुनते ही देश के पिछड़े इलाके में चल रहे लगभग 5 हजार कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में से एक के शिक्षक ख़ुशी से बोल उठे, अब गरीब की बेटियों को अधिक पढ़ने का मौका मिलेगा। दरअसल उनकी ख़ुशी इस बात से जुड़ी थी कि नई शिक्षा नीति की वजह से अब कस्तूरबा में केवल कक्षा 6 से 8 तक नही, बल्कि 12वीं तक की पढ़ाई होगी। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय समाज के वंचित तबके,दिव्यांग,ड्राप आउट हो चुकी बेटियों के लिए है। नई नीति इनके लिए एक वरदान बनकर आई है। अब देश में चल रहे कस्तूरबा आवासीय विद्यालय 8वीं तक नहीं, 12 वीं तक की शिक्षा मुहैया कराएगी। ये कदम दूरदराज के पिछड़े इलाके के लाखों बेटियों को बड़े स्वप्न देखने को प्रेरित करेगी।

इस तरह की कई पहल 34 वर्ष बाद देश को मिली है, नई शिक्षा नीति में देखने को मिली है, जहां स्कूली शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को समझा गया है। कई राज्यों के स्कूलों के साथ काम करने के अनुभव से यह कह सकता हूं कि नई शिक्षा नीति कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी बदलाव आएंगे!

सीखने के स्तर बेहतर करने का राष्ट्रीय संकल्प

नवंबर 2017 में देशभर के लगभग 15 लाख विद्यार्थियों के ऊपर हुए नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं की रपट,सब यही बताती है कि देश के बच्चों में भाषा और गणित की दक्षता कक्षानुसार नहीं है, भारत में लर्निंग क्राइसिस अर्थात सीखने का संकट है और इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान में स्कूली शिक्षा व्यवस्था से जुड़े तक़रीबन 5 करोड़ बच्चें ऐसे हैं, जिन्होंने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नही सीखा है।

नईशिक्षा नीति ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। इसके समाधान के रास्ते सुझाए है। महत्वपूर्ण उपायों में 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता होग। शिक्षा मंत्रालय आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगी, जो राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशों से समन्वय बनाकर क्रियान्वयन योजना बनाएगी, उसे लागू करेगी। यह कदम देश में सीखने के स्तर को बेहतर करने की दिशा में प्रभावी होगा, साथ ही सीखने के स्तर को ठीक करने के राष्ट्रीय संकल्प की तरह सबको अपनी जिम्मेवारी निभाने का भान कराएगा।

शिक्षकों की नहीं होगी कमी

नई शिक्षा नीति में 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री की व्यवस्था होने से केवल शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक युवाओं के आने का रास्ता खुलेगा, वहीं स्नातक के बाद विद्यार्थियों का समय भी बचेगा। अभी तक कई बार शिक्षक होने का विकल्प सबसे आखिरी करियर आप्शन के रुप में देखा जाता है। इस कदम के साथ साथ शिक्षकों के क्षमता संवर्द्धन पर भी अधिक जोर दिया गया है ताकि वे अपनी प्रतिभा का समुचित उपयोग नौनिहालों के लिए कर सकें।

सबसे खास बात है शिक्षकों के खाली पदों को भरने के स्पष्ट लक्ष्य। देश के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों के 2 लाख से भी अधिक पद अभी खाली है। बात प्राइमरी स्कूलों की करें तो वहां पर खाली पदों की संख्या 9 लाख से भी अधिक है। शिक्षकों के खाली पद सबसे अधिक वहां है, जो देश के पिछड़े इलाके है। खासकरजहां वंचित तबके के लोग रहते है। नई नीति ने प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से शिक्षकों के खाली पद भरने पर जोर दिया है।

यही नहीं छात्र-शिक्षक अनुपात को भी बेहतर करने के प्रयास होंगे। अभी 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का प्रावधान है। देश के 112 आकांक्षी जिलों में छात्र-शिक्षक का अनुपात सही नहीं है। इन पिछड़े इलाकों में शिक्षक नियुक्ति की कोशिशें भी विफ़ल रहती है। नई नीति 25 बच्चों पर एक शिक्षक रखने की बात उन इलाकें के लिए करती है, जहां शैक्षणिक दृष्टि से अधिक चुनौतियां हैं। शिक्षक नियुक्ति एवं पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता सीखने के संकट से उबरने में काफी मददगार साबित होगी.

बाल्यकालकी शिक्षा पर अधिक जोर

सितंबर 2019 तक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक तो देश में 1380796 आंगनवाड़ी केंद्र थे। इन केन्द्रों में 6 माह से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग

के तक़रीबन 7 करोड़ बच्चें नामांकित थे। अफ़सोस इन करोड़ों बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र अब तक उचित पोषण सामग्री देने और खेलने-कूदने की जगह ही थी। शिक्षा संबंधी कार्य पर उतना ध्यान नही था। नई शिक्षा नीति ने शिक्षा प्रणाली में बाल्यावस्था की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। अब वे शिक्षा केंद्र के रूप में भी तब्दील होंगे। इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं।

पहली प्रमुख बात है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण! आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में 13,29,138 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 11,85,291 आंगनबाड़ी सेविका कार्यरत है।नई शिक्षा नीति ने 12वीं अथवा उससे अधिक पढ़ी लिखी कार्यकर्ताओं के लिए 6 महीने के विशेष सर्टिफिकेट कार्यक्रम, वहीं बाकी बचे लोगों के लिए एक वर्ष के डिप्लोमा कार्यक्रम का प्रावधान किया है। इस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत कर्मी जब दक्ष होंगे तो वे बालमन को सीखने-समझने में मदद करेंगे।

दूसरी प्रमुख बात ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं

के दक्षता संवर्द्धन के साथ साथ नई शिक्षा नीति 0 से 3 वर्ष तथा 3 से 8 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए अलग - अलग पाठ्यक्रम विकसित करने की बात कही है। इसके लिए वजाप्ता प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षिणिक ढ़ांचा (NCPFECCE)बनाई जायेगी जिसमें भारतीय परंपरा के साथ साथ वैश्विक नवाचारों को भी शामिल किया जाएगा। इससे माता-पिता के साथ - साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी बच्चों के शैक्षिक मार्गदर्शन करने में मदद मिलेगी।

तीसरी प्रमुख बात है कि बाल्यावस्था के शिक्षण हेतु विशेषज्ञ शिक्षक का संवर्ग तैयार होगा, जो नौनिहालों का भविष्य संवारेंगे। साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि कक्षा पहली में जाने से पहले बच्चें बालवाटिका में जाएंगे, जहां उनके लिए विशेष शिक्षक होंगे। शिक्षा नीति में ये प्रावधान छोटे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक बेहद क्रांतिकारी पहल है। 3 से 8 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना जरुरी भी है क्योंकि ये अवधि बच्चों के मानसिक विकास की दृष्टि से उत्तम समय है, जब वे आसानी से नयी बातों को सिखने में अधिक सक्षम होते है।

इसके अलावा आंगनबाड़ियों को स्कूल परिसर के साथ एकीकृत करने की बात भी कही गई है, जो बच्चों को स्कूल परिसर से न केवल परिचय कराएगी बल्कि पहली कक्षा में जाते समय पहले दिन से ही सहज महसूस कराने का काम करेगी। उन्हें स्कूल अंजान नही लगेगा।

ड्रापआउट की समस्या होगी दूर

वर्ष 2017-18 के भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक खपत के प्रमुख संकेतों पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण (एनएसएस) रिपोर्ट की माने तो शिक्षा प्रणाली में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। लेकिन यही रिपोर्ट बताती है कि 3 से 35 वर्ष की आयु वाले 13.6 प्रतिशत लोगों ने कभी स्कूल में नामांकन नही करवाया। जो नामांकित भी हुए उनमें प्राइमरी स्कूलों से 10 प्रतिशत लोग ड्रापआउट हो गए। मिडिल के स्तर पर यह आंकड़ा 17.5 प्रतिशत था जबकि 19.8 प्रतिशत ने माध्यमिक स्तर पर ही स्कूल छोड़ दिया था।

देश के सुदूर ग्रामीण अंचल अथवा वनवासी क्षेत्रों

में स्कूलों से ड्रापआउट होने बच्चों की संख्या देखकर किसकी छाती नही फटेगी। ऐसे अनेकों बच्चों को कई वजहों से स्कूल छोड़ते स्वयं अनुभव किया है। बेहद ख़ुशी की बात है कि नई शिक्षा नीति ने ड्राप आउट की समस्या को रेखांकित किया है और इससे निजात पाने का दिशाबोध कराया है।

ड्राप आउट मुक्त स्कूली शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति स्कूलों को संसाधनों से लैस करने की बात करती है। अधिकतर स्कूलों में ड्रापआउट की वजह शिक्षकों की कमी होती है। शिक्षा नीति शिक्षकों के खाली पदों को उन स्थानों पर भरने पर अधिक ध्यान देने को कहा है जहां काफी चुनौतियां है। व्यवहारिक रुप से अभी दुरस्त इलाकों में पोस्टिंग सजा की तरह देखी जाती है। नई नीति ऐसे इलाकों में जाने वाले शिक्षकों के लिए अलग से विशेष सुविधा देने की बात करती है। यही नहीं, ड्राप आउट को खत्म करने के लिए पाठ्यचर्या में बदलाव और उसे अधिक विद्यार्थी केन्द्रित बनाने की बात भी शामिल है।

अल्पकालीन 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी का मॉड्यूल भी विकसित किया जाएगा ताकि पहली कक्षा में आने वाले बच्चें ड्राप आउट न हो सके। साथ ही उन्हें बुनियादी शिक्षा से जुड़ी जानकारी भी दी जा सकें।

ड्राप आउट की समस्या को दूर करने के लिए नई नीति समाज को भी स्कूल के साथ जोड़ने की वकालत करती है। इसके तहत न केवल नामांकन और ठहराव, बल्कि ड्रापआउट की स्थिति में दुबारा स्कूल से जुड़ने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी।

इन कोशिशों के अलावा जो सशरीर स्कूल जाने में सक्षम नही है, उनके लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान को भी मजबूत बनाये जाने की बात शामिल है, जिसके तहत अब केवल 10वीं और 12वीं ही नहीं, A, B और C कार्यक्रम, जो क्रमशः कक्षा 3, 5 और 8 केबराबर होंगे,भी उपलब्ध कराएंगे। इससे कोई भी व्यक्ति सामाजिक रूप से भी स्वयं को ड्रापआउट की वजाए किसी न किसी कक्षा पास होने के भाव के साथ समाज जीवन में अपना योगदान देगा, जिसे वर्तमान व्यवस्था उसे कमजोर और अनपढ़ के रुप में पहचानती है।

मातृभाषा बनेगी बच्चों की ताकत

यूनेस्को ने 2010 में एटलस प्रकाशित किया था जिसमें भारत के 197 स्थानीय भाषाओं को सूचीबद्ध किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आनेवाले भारतीय भाषा संस्थान ने भी 2013 में देश के अलग - अलग राज्यों के उन 117 भाषाओं की पहचान की जिनका अस्तित्व या तो खतरे में है अथवा निकट भविष्य में समाप्ति के कगार पर है. इसलिए बेहद जरुरी हो जाता है कि देश स्थानीय भाषा को भावी पीढ़ी को सौंपे।

इस दृष्टि से स्कूली शिक्षा में स्थानीय भाषा को प्राथमिकता,विशेषकर संविधान की सूचि में शामिल भारतीय भाषाओं से बालमन को जोड़ने का प्रयास नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बेहद ख़ास बनाते है। भाषाई विवाद को पीछे छोड़ते हुए नई नीति किसी एक भाषा पर जोर देने की वजाए देश में त्रि-भाषा सूत्र लागू करने और कम से कम 2 भारतीय भाषाओं को पढ़ाये जाने की बात करती है। नई शिक्षा नीति के अनुसार कम से कम 8वीं तक स्थानीय भाषा अथवा मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाये जाएंगे। यह एक बेहद जरुरी कदम है।

भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने से और देश की अन्यत्र भाषाओं के अध्ययन के विकल्प से राष्ट्रीय भावना का विकास होगा, अधिक भाषाओं के जानकार राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत बनेंगे।

वोकेशनल शिक्षा से बनेगा आत्मनिर्भर भारत

नई नीति में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए 10 दिवसीय बस्ता मुक्त समय की बात कही गयी है, ताकि वे स्थानीय परिवेश की गतिविधियों यथा बागवानी, बिजली के कार्य, बर्तन बनाने आदि से जुड़ी बातों को समझ पाए, उसका अनुभव ले पाए। वोकेशनल शिक्षा पर जोर देते हुए विशेषज्ञ शिक्षक की बहाली की बात कही गई है। वोकेशनल शिक्षा पर बढ़ावा देने से स्वरोजगार और स्वाबलंबी भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। स्थानीय परिवेश से जोड़कर देने जाने वाली शिक्षा श्रम के महत्व को समझाएगी, वहां की चुनौतियों के समाधान की तरफ ध्यान ले जायेगी, स्थानीय जरुरतों को पूरा करेगा। ■

Understanding the NATIONAL EDUCATION POLICY (NEP)

| Ramanand |

Much discussed and much-hyped National Education Policy (NEP) got cabinet nod yesterday. The current NEP has come after 34 years after a lot of laborious churning. The first committee on NEP was set up in 2015, followed by the second committee in 2017. The chairman of last NEP committee submitted its report on 30th May 2019, and after more than one year of its submission the report has come out in the form of the NEP policy.

The policy has gone through extensive discussion and deliberation overseen by three Human Resource Department (HRD) ministers. It was initiated by Smriti Irani who ran a comprehensive campaign for it and did set the vision for the NEP under her tenure. She did consult all three tiers of Panchayati raj systems viz village panchayat, block panchayat and district panchayat along with people at the state level. During her tenure, the Subramanian Committee submitted its report in April 2016 which soon ran into various controversies. The report thus kept gathering dust at the HRD ministry. When her successor minister Prakash Javadekar assumed charge, a new committee was set-up which again held many consultations with various stakeholders.

What is NEP

NEP, which is now known as the National Education Policy, is a guiding document for both the state and centre. The NEP helps educators and policymakers to shape their views. The first NEP like document came in 1966 under the chairmanship of Prof. D S Kothari. It was a very well-thought document and continues to be a guiding force for various educational initiatives despite not being able to get fully implemented. The second policy for education came in 1986 after 20 years. The plan of action for this policy came into light in 1992 after a long gap of six years. After that, this new NEP is coming after the 34 years, and it also shows the priorities of the government and their concern about education and educational causes.

Key issues of NEP

After the 1966 policy, the new NEP also suggests structural changes right from school education to higher education and regulatory bodies. In school education, it has changed the school education pattern, which was earlier based on 10+2. Now it will be 5+3+3+4 model. It has been said that this system is based on the cognitive stage of the Child and considered more rational. In higher education, it has suggested various changes like multiple exits and entry at degree level

in the university system. In this system, now students can come out certificate/diploma and degree after the 1/2/3 years. Abolition of MPhil, direct PhD after the four years bachelor degree are some of the revolutionary steps.

It has transformed the working of regulatory bodies. Instead of multiple regulatory bodies, only four bodies will now be working to deal with different aspects of education. Existing regulatory bodies like NCTE, ICAR etc. will act as professional standard-setting bodies.

One of the major highlights of the NEP is that it stresses on education in the mother tongue, which is a very significant change. Almost all leading educationists and child psychologists agree that mother-tongue helps in the cognitive development of children. It is a very positive change in a multi-linguistic country like India, where most of the children are forced to study in a language at primary level, which is not their mother tongue.

NEP has touched the untouched part of the education

NEP has proposed that either stand-alone institutions should be transformed themselves in multidisciplinary mode or they have close themselves. This is bold statements. The NEP has given complete freedom to state in many fields. Because education is in the concurrent list, that's why it was always bone of contention with state and centre over the jurisdiction.

National Education Policy has tried to see the education system holistically. It has tried to understand education as a continuous process that why it has put more emphasis connect education to the environment. The NEP has recognized the importance of life skills in the life of human beings, and it has given more attention to developing life skills in the educational process.

NEP has identified the social and gender gap in the education system. NEP has stated that there is a clear gap in the representation of the various social group in the education system. It has highlighted the need to reduce it with all kind of interventions. NEP also identified gender gap in the education system and suggested the mechanism to address it.

NEP is trying to address the quality teaching by improving teaching training institution and by employing more teachers in the education system. The teacher is an essential part of the education system without improving teachers training; we can not improve the quality of education.

National Education Policy has tried to all unaddressed grievances of the education system, which has been not addressed for the decades. This is a historic moment for the all stakeholder of the education system, whether it is teacher, students or parents. The National Education Policy has tried to address everyone's concern in go. It is interesting to see how the state will respond who has major responsibly implement

The Challenge Ahead

The most challenging part of the NEP to implement it in spirit. The finance constraint and state and Center relations will be the biggest hurdles in it.

We all are aware that education is not the only service, but it is also a tool of politics for many regional and political groups. They will not allow implementing some of the recommendations of the NEP as it will undermine their authority. It is a big task for the centre to make state agree with some of its recommendations like closing down stand-alone institutions etc.

The infrastructure issue will be 2nd big challenge for the government as there are not adequate resources for the education field as it is considered a less lucrative filed by industrialists. To provide education, this vast population is not a very easy task, and They need large fund for this. ■

अभाविप की ऑनलाइन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक इंदौर में संपन्न

कोरोना रूपी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को अपने कार्यशैली पर पुनर्विचार करने के लिए विवश कर दिया। कोरोना के कहर के कारण जहां एक ओर लोगों का जनजीवन त्रस्त है वहीं दूसरी ओर संस्थाओं, संगठनों एवं अन्य संस्थानों की कार्यशैली में भी बदलाव ला दिया, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हाल में संपन्न अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक है। विद्यार्थी परिषद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक का आयोजन ऑनलाइन करना पड़ा है।

इंदौर में आयोजित कार्यसमिति बैठक का अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एस. सुबैय्या ने चेन्नई से ऑनलाइन उदघाटन किया। उदघाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी एक भीषण आपदा है, किन्तु इससे हमें सबक भी सीखने हैं। हमें भविष्य में ऐसी बीमारियों से बचने के लिए भारतीयता के मूल्यों स्वच्छता, उचित आहार, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए प्राचीन काल से किये जा रहे आयुर्वेदिक औषधियों के सेवन इत्यादि को अपनाने की आवश्यकता है। इस कठिन घड़ी में देश के नागरिकों, सरकार एवं अभाविप के कार्यकर्ताओं ने कोरोना योद्धा बनकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्कृष्ट कार्य किया। मुम्बई, पुणे तथा इंदौर में अभाविप कार्यकर्ताओं के द्वारा रेड ज़ोन में की गई स्क्रीनिंग की सराहना सर्वत्र हुई। कोरोना ने यह भी दिखाया कि हमारी शिक्षा पद्धति में इस प्रकार की चुनौतियों से लड़ने के लिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो समग्र शिक्षा पर जोर देती है, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वर्ष 2019-20 की सदस्यता ने पिछले सभी रिकार्ड तोड 33 लाख का आंकड़ा किया पार

वर्ष 2019 – 20 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने सभी पुराने आंकड़ो को ध्वस्त कर रिकार्ड 33

लाख से अधिक सदस्यता के आंकड़ों को पार किया। केंद्रीय कार्यसमिति बैठक में बैठक में सम सामयिक मुद्दों जिनमें कोरोना महामारी के कारण छात्र-जीवन में बदलाव, कोरोना से लड़ने में अभाविप का योगदान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं अंतिम वर्ष के छात्रों तथा नीट-जेईई इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं पर चर्चा हुई। अभाविप ने पूर्व के सभी मानको को तोड़ते हुए वर्ष 2019-20 में 33,39,682 सदयस्ता की। यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। जिसका उल्लेख करते हुए अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ऑनलाइन (abvp.org/join) माध्यम से होने वाली सदस्यता हेतु पोस्टर का अनावरण करते हुए सदस्यता अभियान का विधिवत शुभारम्भ किया गया।

कोरोना तालाबंदी के समय विद्यार्थी परिषद के 59939 कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य में भागीदारी की जिसमें 3010951 भोजन पैकेट, 3,17,553 राशन किट, 5,83,689 मास्क वितरण किये गये साथ ही 5,612 यूनिट रक्तदान और 2,86,43,913 की धनराशि पी.एम. केयर फंड में ज़मा किये। (20 मई तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार)

कोरोना महामारी से लड़ने में अभाविप का योगदान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा परीक्षाओं पर हुई चर्चा

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि, "अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोरोना काल में भी छात्रहितों को ध्यान में रखते हुए मा. प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री तथा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा तथा प्रान्तशः हेल्पलाइन नम्बर जारी कर आज भी हजारों छात्रों की सहायता कर रही है। अभाविप ने नीट-जेईई की परीक्षा देने में छात्रों के समक्ष आवागमन एवं परीक्षा स्थल के आसपास ठहरने की समस्याओं को ध्यान में रख कर पूरे देश में हेल्पलाइन नंबर जारी किए तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एवं देश भर के अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों के लिए भी अभाविप ने हेल्पलाइन नंबर जारी की है। कोरोना काल में विद्यालय बंद हैं अतः छात्रों शैक्षणिक हानि ना हो इस हेतु अभाविप देशभर में परिषद की पाठशाला नामक अभियान के द्वारा बस्ती तथा गावों के छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ■ ■

Strict action against the proprietors of fake universities required : ABVP

7 out of 24 fake universities declared by the University Grants Commission (UGC) are located in Delhi. Fraudulent practices like these in the field of education can cause irreparable harm to the students and remain a major object of concern. Delhi, being a major educational hub, attracts students as well as competitive exam aspirants from all corners of the country. Continued vigilance from the authorities as well as individuals is required to prevent a repeat of similar events and safeguard the interests of students in the times to come.

Sidharth Yadav, State Secretary, ABVP Delhi, said, "A total of seven fake universities have been discovered in Delhi. Frauds of this nature and scale in the national capital continue to remain a major cause of concern. The students enrolled in these fake universities have been left in the lurch. The situation warrants strictest possible action against the management and proprietors of such fake universities. Alternatives must be explored to help the affected students continue their studies without any unreasonable delay. It is incumbent upon the government to remain vigilant and take swift action against those willing to play fast and loose with the careers of unsuspecting students." ■

THE PROPOSAL TO HOLD A JOINT ENTRANCE EXAM FOR CENTRAL UNIVERSITIES IS A WELCOME MOVE: ABVP

Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad welcomes the proposal to hold a Joint Entrance Exam for admission to undergraduate courses in Central Universities from the session 2021-22. The proposal to hold a Joint Entrance Exam is in the interest of students. The proposal to hold a common Joint Entrance Exam for students seeking admission to undergraduate courses, similar to the IIT JEE and NEET will provide economic, mental, physical relief for students and reduce the consumption of time, making the process hassle free.

Nidhi Tripathi, National General Secretary, ABVP, said, "The proposal to hold a joint entrance exam for admission to central universities will make admissions to subjects like science, commerce and humanities much simpler. It will felicitate the creation of a knowledge based educational environment, reduction of financial stress of the guardians, and will bring about an end to the race to just secure maximum marks and pave way for the students to study subjects of their choice." ■

अभाविप प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय राज्यमंत्री कैलाश चौधरी को सौंपा ज्ञापन, कृषि शोध से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग

सात अक्टूबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली, एग्रीविजन और आईएआरआई (भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान) के छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी से मुलाकात की। इन्होंने कोविड-19 की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए चौथे वर्ष के शोध छात्रों हेतु फेलोशिप की समय-सीमा में विस्तार की मांग को लेकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा।

कोविड-19 और लॉकडाउन की परिस्थिति ने छात्रों के प्रयोगशाला कार्य (लैब वर्क) और रिसर्च कार्यों को प्रभावित किया है, जिस कारण छात्रों के समक्ष पीएचडी पूरी करने में बाधा उत्पन्न हुई है। इस विषय को प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा है।

केन्द्रीय राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल के अनुरोधों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और डीजी आईसीएआर के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की। अभाविप ने केन्द्रीय राज्यमंत्री कैलाश चौधरी को इस संवेदनशील समय में छात्रों के भविष्य और करियर की स्थिति के बारे में विचार करने के लिए एक पत्र सौंपा है।

पत्र में वर्तमान कोविड-19 स्थिति के परिणामस्वरूप आईएसीआर/आईएआरआई के छात्रों द्वारा निर्धारित समय के भीतर प्रतिबद्ध शोध कार्यों को पूरा करने की असमर्थतता, छात्रों के समक्ष रसायनों की अनुपलब्धता, तकनीकी सहायता में कमी जैसी अनेकों समस्याओं के विषय को रखा गया है। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया की कई छात्रों को अपने पूरे शोध कार्य को दोबारा से शुरू करना पड़ सकता है। इन्हीं कारणों से छात्रों को शोध कार्यों को पूरा करने हेतु एक और वर्ष की आवश्यकता है।

अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव का कहना है कि," हम शोध छात्रों की समस्याओं को अलग-अलग निकायों के सामने लगातार रख रहे हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़े शोध कार्य चूंकि प्रयोगशाला से जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से कोविड-19 के कारण उनका प्रयोगशाला का कार्य प्रभावित हुआ है ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं। आज की हमारी वार्ता सकारात्मक रही है, हम आशा करते हैं कि शीघ्र हमने कृषि शोध से जुड़ी जिन समस्याओं को उठाया है उस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।" प्रतिनिधिमंडल में एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव, एग्रीविजन दिल्ली इकाई के संयोजक रोहित और आईएआरआई के छात्र शामिल रहे। ■

अभाविप की अनूठी पहल 'परिषद की पाठशाला'

| अजीत कुमार सिंह |

2019 के अंतिम महीनों में चीन के वुहान में एक कोविड – 19 नाम का वायरस आया, जिसने सबसे पहले चीन को और बाद में पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लिया। कोविड – 19 यानी कोरोना के कारण के पूरी दुनिया अस्त – व्यस्त हो गई। इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारी जीवनशैली इस कदर बदल जायेगी। कोरोना के कारण हो रही मौतें और इसके प्रसार को देखते हुए कई देशों ने अपने यहां लॉकडाउन (तालाबंदी) करना शुरू किया, अपने देश के नागरिकों से अपील की गई कि जो जहां हैं वहां रहे, बिना अति आवश्यक कार्य के घर से बाहर न निकलें। मार्च आते – आते भारत में भी कोरोना का असर दिखने लगा। भारत सरकार ने भी अंततः 22 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया। एक सौ तीस करोड़ का यह देश ठहर गया। कोरोना के कारण पूरा जीवन अस्त – व्यस्त और त्रस्त हो गया। स्कूल – कॉलेज, मॉल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि सभी स्थल बंद कर दिये गये। या यूं कहें स्वास्थ्य एवं जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी के दरवाजे पर ताले बंद हो गये।

शुरूआत में लॉकडाउन के कारण भारत में स्थिति खराब हुई लेकिन बाद में सरकार के सुझबुझ और सक्रियता ने लोगों को काफी राहत पहुंचाई। शहरों से लोग अपने घरों को जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। छात्रों ने कुछ दिनों तक छात्रावासों में समय जरूर गुजारा परंतु अप्रवासी छात्रों का धैर्य तब जवाब देने लगा जब उनके राशन और पैसे खत्म हो गये। देश भर के लोग अपने घरों में थे लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने जान की परवाह किये बगैर लोगों की सहायता कर रहा था। छात्रावासों में फंसे छात्रों को भोजन समेत जरूर सामानों को पहुंचाने, पैदल चल पड़े लोगों की मदद करने की बात हो या सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की सेवा करने की बात... हर जगह परिषद के कार्यकर्ता डटे रहे। लॉकडाउन के बाद सरकार के द्वारा जब कुछ ढील दी गई तो अभाविप के कार्यकर्ताओं ने अप्रवासी छात्रों को

उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था की। कोरोना काल में अभाविप के द्वारा किये गये सेवा कार्य का उल्लेख यहां कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए अलग से आलेख लिखना होगा। कोरोना के कारण अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई क्षेत्र हुआ तो वह है शिक्षा क्षेत्र। कोरोनाकाल में बंद पड़े महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन ने ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान किया है लेकिन साधनहीन विद्यालय के छात्र, जिनके पास न एंड्राइड मोबाईल और न ही ऑनलाइन की कोई सुविधा, वैसे विद्यालयीन छात्रों के भविष्य को देखते हुए बस्तियों में रहने वाले छात्रों के लिए अभाविप द्वारा परिषद की पाठशाला का आयोजन किया गया। स्कूली छात्रों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा 'परिषद की पाठशाला' नाम की अनोखी मुहिम चलाई गई। इस अभियान के तहत महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ती में ही पाठशाला लगा दिया।

अभाविप के जुड़े छात्रों ने अपनी पढ़ाई की चिंता किये बगैर गरीब और जरूरतमंद बच्चो के भविष्य को संवारने में जुट गये। देशभर में विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगभग 800 बस्ती की पाठशालाएं चलाई जा रही है जिनमें दस हजार से अधिक बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़े रखा गया है। इस दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा न केवल उन्हें शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि जरूरतमंद छात्रों को पेंसिल, स्टेल, कॉपी व अन्य जरूरी चीजें भी दी जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाजर भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। ये पाठशालाएं अनलॉक होने के बाद से ही चलाई जा रही है। परिषद की मानें तो जब तक विद्यालय समान्य तरीके से नहीं खुलने लगते हैं तब तक ये लगती रहेंगी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी 'परिषद की पाठशाला' के बारे में जानकारी देते हुए बताती हैं कि इसे प्रयोग के तौर पर बिहार में आजमाया गया, जिसके सुखद परिणाम सामने आए। इसलिए इसे पहले के तौर पर पूरे देश में लागू करने का फैसला किया गया। फिलहाल दो हजार से अधिक छात्र – छात्राएं सेवा बस्तियों व ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंद बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये कक्षाएं दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश समेंत देश के लगभग सभी राज्यों के दो सौ से अधिक जिलों में चल रही है। निराशा से घिरे बच्चों के लिए परिषद की पाठशाला उम्मीद की किरण बन चुकी है। महानगरों से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक यह अभियान जारी है ।

सबसे बड़ी बात यह है कि बस्ती में पाठशाला का आयोजन कर बच्चों को पढ़ाने वाले अधिकांश विद्यार्थी वर्ग से हैं जो खुद पढ़ रहे हैं। जिनमें से स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध से जुड़े कई छात्र हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि उनके विश्वविद्यालय कब खुलेंगें। खुद पढ़ते हुए ये छात्र स्कूली छात्रों के भविष्य को संवार रहे हैं। कहीं – कहीं तो अभाविप के दायित्वान कार्यकर्ता खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बकायदा इसके लिए रोस्टर बनाए गए हैं। उपलब्धता और सुविधा के अनुसार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अलग – अलग दिन पढ़ाने जा रहे हैं। अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री खुद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के नजदीक सेवा बस्ती मधुकर में बच्चों को पढ़ाने जाती हैं।

गौरतलब है कि सेवा बस्तियों में अधिकतर गरीब और मजदूर परिवार रहते हैं, जिनके पास ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़ने संसाधन नहीं हैं। जिनके अभिभावक का पूरा दिन दो जून की रोटी के जुगाड़ में बीत जाता है। ऐसे क्षेत्र के बच्चों के लिए परिषद की पाठशाला वरदान साबित हो रहा है। कोरोना को देखते हुए ये पाठशालाएं छोटे – छोटे समूह में आयोजित हो रही है।कोराना के कारण हमारे जीवनशैली में भी काफी आ गया है। वर्चुअल एवं ऑनलाइन कक्षाओं की मांग बढ़ गई है। बड़ी – बड़ी कंपनियां आजकल अपनी बैठक ऑनलाइन ही कर रही है। यहां तक कि हाल में संपन्न अभाविप की केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक का आयोजन भी ऑनलाइन ही हुआ है। कोरोना के कारण मजबूरी में सही लेकिन कई विकल्प सामने आये हैं। साधन संपन्न लोगों के लिए तो यह बड़ी बात नहीं है। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि कई राजनीतिक संगठनों द्वारा सरकार के कदम का आलोचना की गई। अनेक समस्याएं गिनवाई गई लेकिन समस्या के समाधान के साथ कोई संगठन कोई आगे आया तो वह था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। यही कारण है आज अभाविप शैक्षिक परिसर से आगे निकलकर सामाजिक संगठन के रूप में स्थापित हो चुका है। ■

New Education Policy: A Vision for Holistic Development through Vocational and Higher Education

Prof. Ashutosh Kumar Singh

According to great philosopher Confucius "If your plan is for one year, plant rice; If your plan is for ten years, plant tree; If your plan is for 100 years educate children". Macaulay was aware that India could be a threat to the British empire, and he planned to destroy the Indian mindset. The British government imposed an education policy to brainstorm Indian youth through education and named it Macaulay's education policy. A new education policy was the need of the hour for Independent India. However, the first Government of Independent India failed to implement the new education policy, and it continued with the Macaulay's education policy. The responsibility of introducing a new education policy was on the shoulders of two gentlemen, i.e., India's first prime minister and education minister. They could have reformed the existing education policy, but it seems that the education was not on the priority of Pt. Nehru's cabinet. They continued with the implementation of Macaulay's education policy, which develops the slavery mindset. The country waited for 21 years for its first education policy, approved in 1968 by the Govt. of India led by Late Smt. Indira Gandhi. Then, the second education policy was introduced in 1986 by Late Shri Rajiv Gandhi's cabinet which was later modified during Shri P V Narsimha Rao government in 1992. Now, a new education policy is launched after 28 years.As per the new policy, the government will spend 6% of GDP on education, which was 1.7% only before this policy.

On July 27, 2015, the NDA government

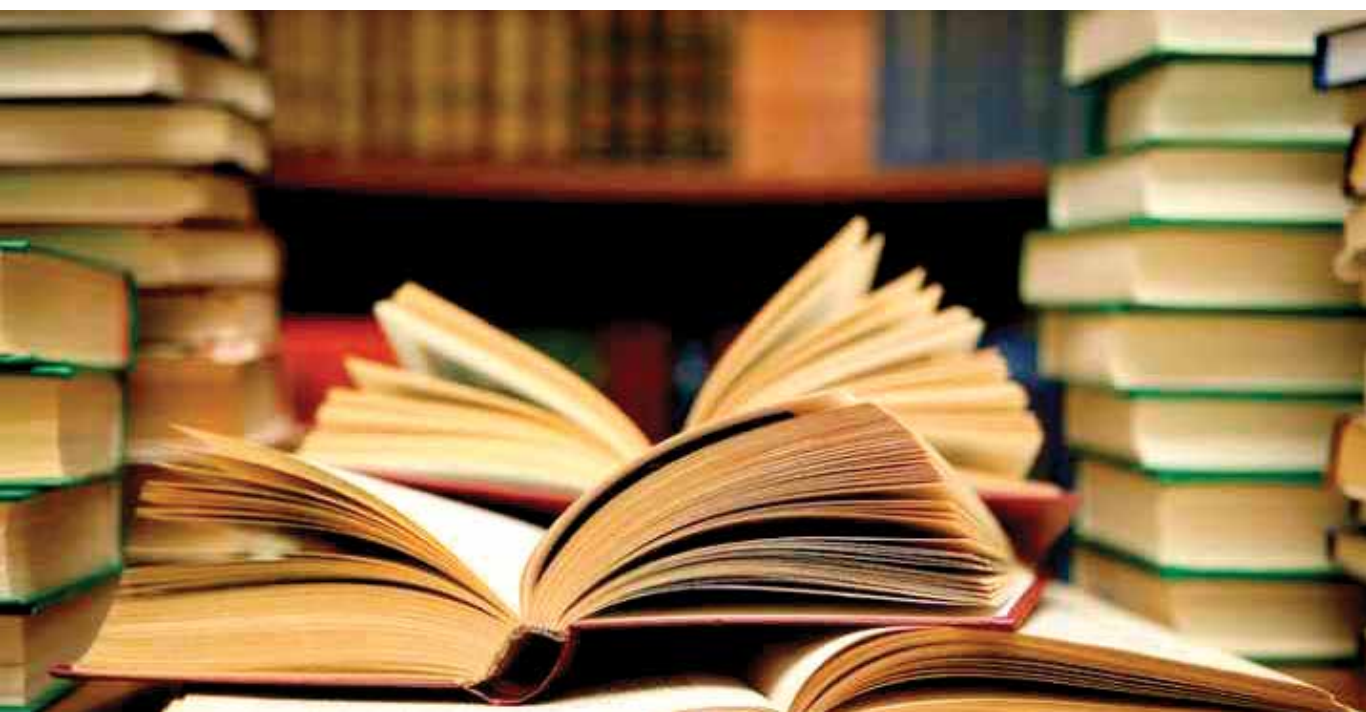

led by honourablePrime Minister Shri Narendra Modi started planning to introduce a new education policy that can meet the requirements of the changing world. A committee was formed to propose the education reforms under the chair of TSR Subramaniam in 2015. The TSR Subramaniam committee submitted a draft proposal of

484 pages to the Govt. of India on October 1, 2016. The proposed draft went through a series of modifications after receiving the suggestions of students, teachers, industries, etc. across the nation. Finally, the draft of the new education policy was submitted by Dr. K. Kasturirangan committee to the HRD minister, Govt. of India. The Govt. of India introduced the New Education Policy 2020 on July 29, 2020, covering the details in a 66-page document.

The well-equipped armed forces symbolize the strength of the nation; the USA is a great example. From ancient times to the modern world, technology has been impacting the results of wars. For instance, Mughal intruders defeated Indian Rajputana's with the help of Cannon as Rajputana's were using only swords and Javelins only. On a similar note, India witnessed a defeat against its first war against China in 1962. Thus, it can be said that the war at any level has been a great source of development of new technologies. The existing education policy does not worry about innovative research and development. Fortunately, the Government of India introduced the new education policy in 2020 to encourage the innovation among Indian youth. The new policy aims for the transformational reforms in the education system at primary and higher education levels across the country.

New policy targets to achieve the universalization of education from pre-school level to secondary level in school education by 2030. It is expected to bring about 20 million out of school children back into the mainstream through the open schooling system. The new policy replaces the existing 10+2 system by a new 5+3+3+4 structure corresponding to ages 3-8, 8-11, 11-14, and 14-18 years. The new system will have 12 years of schooling with three years of Anganwadi/ pre-schooling.The new policy encourages teaching in mother tongue and/or regional language up to Grade 5. Similarly, the National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE-2021) will be formulated by the NCTE in consultation with NCERT. The new policy will also introduce the minimum degree qualification for teaching by 2030 i.e., 4-year integrated B.Ed. degree.There is no rigid separation between academic streams, and vocational education will be introduced from Class 6 with Internships. The benefits of vocational training would be immense. According to the new policy, every student would have to learn at least one vocation and may be exposed to many others. The important aspect of the policy is that the states are given the responsibility to choose the vocational trainings; for instance, Bihar state can introduce flood management or mining as vocational training. The 10-day bagless period is introduced for 6-8 grades to mandate the internships which may be continued further throughout 6-12 grades. In addition, the government has allowed

the online vocational training to meet the today's worldrequirements i.e. digital and online learning. The digital and online learning platform will ensure the learning as per student's time and pace. Also, National Testing Agency (NTA) will offer high-quality common aptitude test at least twice every year for university entrance examination.

In higher education, the government has raised the gross enrolment ration t0 50% by 2035 i.e. 35 million additional seats will be introduced in higher education. The policy emphasizes on making higher education multi-disciplinary, holistic undergraduate education with flexible curricula, creative, idea-based-application, vocational education. The new education policy focuses on developing the large multidisciplinary universities such as Takshashila, Nalanda, Vallabhi, and Vikramshila in ancient times. It will increase the multidisciplinary research environment to create innovative individuals to transform the nation educationally and economically. It also implements a flexible curriculum through multiple entry and multiple exit system. The students will be provided with appropriate certification based on completed credits. Higher education will be monitored by a single body i.e., Higher Education Commission of India (HECI). The HECI will have National Accreditation Council (NAC), Higher Education Grants Council (HEGC), General Education Council (GEC), and National Higher Education Regulatory Council (NHERC), which will be responsible for accreditation, funding, standard setting, and regulation, respectively. There will be no difference in the norms for public and private institutions. The new policy also emphasizes fostering the research across the higher education institutions and suggests to create the National Research Foundation (NRF) as an apex body to achieve the task. The new policy advocates to phase out the culture of affiliated colleges in the next 15 years. The institutes will get financial autonomy as well. Another exciting part of the new policy allows Indian universities to open their overseas campuses, and it will also encourage the top universities across the globe to open their campuses in India. The objective is to promote India as a global study destination by providing the premium education at affordable costs. Thus, India will restore its role as a Vishwa Guru. With these enormous reforms, the new education policy will not only boost the quality of Indian education, but it will also help in the holistic development of an individual. Apart from this, it may also help in increasing the Indian economy as it will attract foreign investments in India.

The advancement in technology plays a critical role in the prosperity of a nation, technology advances through quality research, and quality research can be conducted through critical thinking. The new education policy gives the hope to make it happen. ■

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' नवम्बर 2020 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti

पटना : शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन के संकल्प साथ संपन्न हुआ विश्वविद्यालय छात्र नेता सम्मेलन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बिहार के सभी विश्वविद्यालय में छात्र नेता सम्मेलन का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा छात्र नेता सम्मेलन में बिहार के सभी 11 विश्वविद्यालय के सभी 37 जिले के 897 ,जिसमे 746- छात्र ,122 -छात्राओं, 24 -शिक्षक समेत बिहार के प्रमुख छात्रनेताओं ने भाग लिया । बिहार के सभी विश्वविद्यालय में छात्र नेता सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न विषयों के ऊपर छात्र नेताओं के द्वारा चर्चा की गई तथा विभिन्न मुद्दों को उठाया गया ।

अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास ने उपस्थित छात्र - छात्राओं को राष्ट्र, धर्म तथा समाज के प्रति उनके दायित्व से परिचित करवाते हुए कहा कि छात्र नेताओं को सेना की तरह तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देश की सेना सीमा पर हमारे देश की रक्षा बाह्य आक्रमण तथा आतंकवादियों से करती है, ठीक उसी प्रकार हमें समाज के अंदर अपने शैक्षणिक संस्थान को तथा समाज को बौद्धिक आतंकवाद फैलाने वाले तथा अर्बन नक्सल को बढ़ावा देने वालों से बचाने के लिए मुस्तैद रहना होगा। उन्होंने कहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत का एक ऐसा छात्र संगठन स्थापित हुआ जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता व महान संस्कृति से प्रेरित होकर भारत को एक महाशक्तिमान समृद्धिशाली एवं स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में पुननिर्मित कर उसे राष्ट्रमालिका में गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के भव्य लक्ष्य से प्रतिबद्ध है ।

वहीं अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन जी ने आयोजित छात्र नेता सम्मेलन में कहा कि बिहार विद्यार्थी परिषद ने हमेशा देश को नई दिशा दिखाने का काम किया है।1975 का आंदोलन इसका प्रमाण है । जब सत्ता के मद में चूर सरकार ने देश में आपातकाल थोपा था तब बिहार विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बाद में यह आंदोलन संपूर्ण क्रांति के रूप में परिवर्तित होकर पूरे देश में फैल गया।

प्रदेश मंत्री लक्ष्मी रानी ने कोरोना काल में परिषद द्वारा किए गए सभी प्रकार के सेवा कार्य का विवरण रखा गया, जिसमें पीएम केयर्स फंड में बिहार विद्यार्थी परिषद के द्वारा 36 लाख दान देना, मास्क का वितरण, भोजन सामग्री तथा गांव के अंदर सेनीटाइजर, परिषद की पाठशाला को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हुआ । शिक्षण संस्थानों के शुल्क माफी, रूम रेंट माफी आदि विषय पर आंदोलन छात्रों एवं अभिभावकों को स्थाई समाधान मिलने तक मिलने तक संघर्ष की बात दोहराई।

प्रदेश संगठन मंत्री डॉ सुग्रीव कुमार ने छात्र नेता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा बिहार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने समाज के अंदर समरसता के भाव साथ काम करते हुए इस बढ़ती सामाजिक खाई को पाटने का काम किया था ।बिहार विद्यार्थी परिषद ने भीषण जातीय हिंसा जो 1998 में हुआ था,उस वक्त भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए समाज के अंदर से इस प्रकार के विभेद को खत्म करने का प्रयास किया था। प्रदेश सह संगठन मंत्री अजीत उपाध्याय ने छात्र नेता सम्मेलन के माध्यम से राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार एवं सभी

प्रशासन को आश्वस्त किया कि इस कोरोना कि संकट की घड़ी में हमारा एक कार्यकर्ता सकारात्मक व समाज हित में दिए गए सभी निर्णय में पूर्णतः सहयोग के लिए कटिबद्ध है ।

केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य सुजीत पासवान व पूर्व प्रदेश मंत्री भरत सिंह जोशी ने विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा बौद्धिक कार्यक्रम ,विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन जो ऑनलाइन सम्पन्न हुआ, का भी उल्लेख किया । इस दौरान कोविड-19 के इस भीषण महामारी में अभाविप की भूमिका, सेवा कार्य समेत संगठन कार्य तथा उन्हें मिलने वाली चुनौतियां,छात्र संघ की भूमिका, छात्रा कार्य, आंदोलनात्मक गतिविधि, रचनात्मक कार्य, ऑनलाइन कार्य ,शोध कार्य, विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय में छात्राओं की स्थिति तथा उनकी चुनौतियां ,महिला सशक्तिकरण, मिशन साहसी जैसे मुद्दों के साथ स्थानीय सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक ,आर्थिक तथा रोजगार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई तथा इन मुद्दों को विभिन्न प्रकार से उठाया गया। बिहार के पूरे विश्वविद्यालय में आयोजित छात्र नेता सम्मेलन में निम्न विषयों पर आधारित प्रस्ताव पास किए गए।

विश्वविद्यालय छात्र नेता सम्मेलन को थिंक इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक गौरव सुंदरम, प्रांत छात्रा प्रमुख वंदना भगत, सह छात्रा प्रमुख अंजना सिंह, प्रदेश सह मंत्री अंशिका सिंह,मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ आलोक कुमार , महासचिव प्रीति कुमारी,कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष गौरवी सिंह, समेत सभी प्रमुख छात्र नेता ने सम्मेलन को सम्बोधित किया । ■

नशाखोरी परिसर संस्कृति को भंग करने वाली, देश भर में हो नशे पर व्यापक बहस : अभाविप

सुशांत राजपूत की मौत के बाद नशे पर बहस शुरू हो चुकी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि देश भर में नशे के विषय पर व्यापक बहस होनी चाहिए। विज्ञप्ति में परिषद ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला राष्ट्र भारत, युवाओं में नशाखोरी एवं ड्रग्स के सेवन की समस्या सामने आ रही है। नशीले तत्वों का दंश देश के शैक्षिक परिसरों पर भी हावी है। इसे बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़ा हाथ देश के मनोरंजन उद्योग का भी रहा है। सितारों द्वारा नशे के सेवन को "कूल" एवं स्वच्छंदता के प्रतीक की तरह फिल्मों, गानों, टीवी एवं वेब सीरीजों में दिखाए जाना एवं अपने निजी जीवन में भी ऐसे मादक पदार्थों का सेवन युवा वर्ग के सम्मुख एक आभासीय प्रतिष्ठा का गलत उदाहरण पेश करता है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मानती है कि नशाखोरी परिसर संस्कृति को भंग करने वाली एवं युवाओं में ही नहीं अपितु पूरे परिवार में अशान्ति का कारक बनती है। नशीली दवाइयों का सेवन प्राणघातक तक साबित होता है जो देश के भविष्य पर कुठाराघात है।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि मेरा इस देश के युवाओं से आवाह्न है कि वो सही आदर्श चुनें एवं 'नशा मुक्त पर्यावरण युक्त स्वस्थ भारत' बनाने की दिशा में कार्य करें। समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए और व्यापक चर्चा करनी चाहिये कि नशाखोरी किस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक जीवन के लिए नुकसानदायक है। सिनेमा की ज़िम्मेदारी समाज को दिशा देने की भी है। नशे के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रचार के लिये फ़िल्म जगत से जुड़ा समुदाय भी ज़िम्मेदार है। सिनेमा जगत को तय करना होगा की वे समाज के सामने प्रेरणादायी छाप छोड़े।

वहीं अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री अनिकेत ओव्हाल ने मुंबई में चल रहे प्रकरण में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच करते हुए मुम्बई फ़िल्म जगत के अंदर जिस प्रकार नशे का पूरा गिरोह सामने आ रहा है उसकी समुचित जांच होनी चाहिए तथा नशे के इस कारोबार के फलने - फूलने के लिए जिम्मेदार सभी दोषियों पर उचित करवाई होनी चाहिए। ■

अभाविप के नेतृत्व में खेल मंत्री से मिला पर्वतारोहियों का प्रतिनिधिमंडल

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में पर्वतारोहियों का एक प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्र राज्य मंत्री किरेण रिजिजू से शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में अभाविप प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव के साथ – साथ पर्वतारोही सौरभ किट्टू टांक, मेघा परमार तथा शोभित शर्मा थे। सौरभ किट्टू टांक ट्रांसजेंडर है,सौरभ किट्टू टांक भारत की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर हैं जो 6000 मीटर की वर्जिन पीक तक पहुंची है। किट्टू इसके साथ ही भारत की पहली ट्रांसजेंडर(किन्नर) है जिन्होंने आईएमएफ (इंडियन मांउटेनिंग फेडरेशन) द्वारा परमिट माउंटेन एक्सपीडिशन में हिस्सा लिया है। यह वर्जिन पीक स्पिती वैली में है, जहां का औसतन तापमान -15c होता है। मेघा परमार देश की जानी-मानी पर्वतारोही हैं , वे मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्त्ता रही हैं ।

अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव ने कहा कि आज युवा एवं खेल मामलों के केन्द्रीय राज्यमंत्री से हमारी शिष्टाचार भेंट में हमारी विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा रही । ट्रांसजेंडरों को मुख्यधारा में स्थान मिले इसके लिए अभाविप सदैव प्रयासरत रही है । अभाविप की कार्यकर्ता मेघा परमार, सौरभ किट्टू की कोच रही हैं तथा उनकी देखरेख में सौरभ ने एक नया मुकाम हासिल किया । यह अभाविप के लिए गर्व का विषय है कि अभाविप कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं । हमने आज की मुलाकात में वर्कप्लेस में ट्रांसजेंडरों के उचित समावेशन पर मंत्री से चर्चा की । हम आशा करते हैं कि सरकार तथा समाज दोनों ही, ट्रांसजेंडरों के शैक्षिक क्षेत्र में उचित अवसरों को दिलाने के लिए आगे आएंगे। ■

कृषि अधिनियम किसानों के हित में: अभाविप

केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया कृषि अधिनियिम - 2020 आम किसानों के हितों को संरक्षित व संवर्धित करते हुए व्यापक रूप से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास की बात करता है। यह बिल वर्षों से मंडियों में चल रहे किसानों के शोषण को समाप्त कर, बिना किसी बंधन के मुक्त रूप से उन्हें फसल बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ लोगों द्वारा बिल के संबंध में कृषक समाज में अनावश्यक शंका एवं भ्रम उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभाविप सरकार से यह मांग करती है कि शीघ्रातिशीघ्र किसानों की शंकाओं को दूर करने का कार्य किया जाये।

ये अधिनियम एक देश एक बाजार की बात करते हैं जो कि किसानों के उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इससे जहाँ एक तरफ कृषक समाज को अपनी उपज देश में कहीं भी उचित दाम पर बेचने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ बिचौलियों के शोषण से मुक्ति भी मिल सकेगी। अभाविप कृषि क्षेत्र से जुडे हुए व्यवसायियों, छात्रों एवं समाज के अन्य वर्गों से यह आग्रह करती है कि वे इन अधिनियमों को जमीन पर क्रियान्वित करने में केंद्र एवं राज्य सरकारों की हर सम्भव सहायता करें तथा देश के अन्नदाताओं के उत्थान एवं उन्नति में अपनी भूमिका का सम्यक निर्वहन करें।

अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री राहुल वाल्मीकि ने किसानों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि "कृषि अधिनियमों के पारित होने के पश्चात अन्नदाताओं के मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न की गई गयी हैं जिन्हें दूर करने का हर सम्भव प्रयास केंद्र सरकार को तुरंत करना चाहिए। कृषक समाज को चिंता मुक्त होना चाहिए क्योंकि ये अधिनियम उनसे उनके अधिकार छीनता नहीं है परंतु उन्हें और शक्तिशाली बनाता है।"

अभाविप के कृषि विद्यार्थी कार्य के संयोजक गजेंद्र तोमर ने कहा कि, "एक राष्ट्र, एक बाजार की माँग कृषक हित में लंबे समय से उठायी जाती रही है। कृषक हमारे देश के अन्नदाता हैं और उनके हितों पर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति विपक्ष की कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करती है।" ■

Recent Farm Bills 2020 – Ensuring sustainability and profitability of farming community

| Suraj Bhardwaj & Gajendra Tomar |

India's Ministry of Law and Justice issued ordinances that will liberate existing market restrictions, eliminate free trade barriers in agricultural production, and empower farmers to engage directly with potential buyers in advance of harvest. The ordinances follow a June 3, 2020 Union Cabinet announcement approving three policy resolutions to further reform domestic agricultural marketing systems to support farmer income. Previously, on May 15, 2020, Finance Minister Nirmala Sitharaman had announced major market reforms as part of the Special Economic Package to stimulate India's agricultural sector in the post-COVID-19 economy.

Early-on in the nearly three-month nationwide lockdown that started in late March, supply chain disruptions exposed critical infrastructure gaps and governance issues regarding the competitiveness of India's agricultural sector. Understanding that the COVID-19 crisis presented an opportunity to improve some of these marketing systems which Indian farmers were required, by law, to use, the Government of India (GOI) proposed major policy reforms to remove many of the long-standing hurdles constraining agricultural growth and farmer income. Specifically, in the third tranche of the economic package, the FM proposed to deregulate major food crops from the 1955 Essential Commodity Act (ECA); allow farmers to sell their agricultural products outside of government-regulated markets; and permit barrier-free inter and intra-state trade of farm commodities. The government also proposed providing a legal framework for farmers to facilitate contract-pricing schemes with processors and other market actors in the supply chains to reduce price risk.

The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020

- Per the GOI, this ordinance will create an environment where farmers and traders will have the ability of free choice of sale and purchase of agricultural products.
- It will also eliminate barriers to inter- and intra-state trade and commerce outside physical market premises, which are normally regulated by state government Agricultural Produce Market Committees (APMCs).
- The ordinance aims to create additional trading opportunities outside established APMC market yards to help farmers get more competitive prices due to additional competition.
- It is crucial to note that the idea is not to close APMC operations but to expand a farmer's choices. So, if a farmer believes a better deal is possible with some other private buyer then he can take that option instead of selling in the APMC mandi.

The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020

- The GOI's press release states that this ordinance will empower farmers to engage with processors, wholesalers, aggregators, wholesalers, large retailers, and exporters

on a level playing field without any fear of exploitation.

- It will transfer the risk of market unpredictability from the farmer to the sponsor and also enable the farmer to access modern technology and better inputs.
- It will reduce the cost of marketing and improve farmer incomes.
- This allows economic agents to stock food items freely without the fear of being prosecuted for hoarding.

The Essential Commodities (Amendment) Ordinance 2020

- Under this ordinance, basic food items including cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onions, and potatoes will be removed from the list of essential commodities, which will help address private investors' concerns of excessive regulatory interference in their business operations.
- The ordinance specifies that these commodities can only be regulated through stock limits under situations such as war, famine, extraordinary price fluctuations, or natural calamities.
- However, agricultural processors and exporters will remain exempted from stock limit impositions even under these "catastrophic" conditions.
- ECA-2020 provides a framework for farmers to enter into contract farming — that is signing a written contract with a company to produce what the company wants in return of a healthy remuneration.

All three Bills are to liberalize the farm markets, which will make the system more efficient and allow better price realizations for all concerned, especially the farmers. The central concern, presumably, is to make Indian farming a more remunerative enterprise. ■

खबर

कानपुरः विकासार्थ विद्यार्थी ने चलाया यमुना स्वच्छता अभियान

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कानपुर के द्वारा 'आयाम विकासार्थ विद्यार्थी' के बैनर तले यमुना नदी को साफ करने का अभियान चलाया गया। विकासार्थ विद्यार्थी के संयोजक अंशुमान वर्मा ने कहा कि नदियां धरती पर प्रकृति के द्वारा मिला वरदान है, इसे स्वच्छ रखना हम सभी का मूल कर्तव्य है। यमुना की साफ - सफाई के लिए भी सिर्फ सरकारों को ही नहीं बल्कि समूचे जनमानस को आगे आना पड़ेगा। हम सरकार से आशा करते हैं कि वे जल शोधन संयंत्र स्थापित कर तथा कूदिया अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा । स्वच्छ पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा संदेश महात्मा गाँधी ने भी दिया था था। विकासार्थ विद्यार्थी यमुना और उसके घाटों की साफ-सफाई के इस अभियान को हर माह चलाकर इसे एक बड़ी मुहिड़ा निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था कर नदी की स्वच्छता के लिए प्रयास करेगी । उन्होंने कहा कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर विकासार्थ विद्यार्थी कानपुर प्रांत के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। स्वच्छता अभियान में छात्रों ने हिस्सा लेकर यमुना घाट से कूड़े को साफ किया तथा इकट्ठा हुए कूड़े का निस्तारण किया । हमलोगों ने नदी में बह रहे पालीथीन व अन्य गंदगियां को बाहर निकालकर दूर गड्ढा बनाकर उसी में अंदर डालकर बन्द कर दिया। अभाविप तथा विकासार्थ विद्यार्थी ने हर माह इस क्षेत्र में सफाई अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है, जिससे कि यमुना की स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जा सके । भविष्य में छात्रों युवाओं को और बड़ी संख्या में अभियान से जोड़ यमुना स्वच्छता अभियान को और तेज करने की योजना है ।

वहीं विकासार्थ विद्यार्थी के सह संयोजक संस्कार गुप्ता ने कहा कि विकासार्थी प्रकल्प के माध्यम से हम कार्यकर्ता प्रकृति व पर्यावरण को लेकर समाज को जागरूक करने की भूमिका का निर्वहन करते हैं। डॉ पद्मा त्रिपाठी व वरुणा दुबे ने कहा कि यमुना नदी में स्वच्छता अभियान चलाकर इस माध्यम से हम सभी समाज व देश वासियों को प्रकृति की सुरक्षा के कर्तव्य के प्रति जागरूक होने की अपील करने की है। ■

हैदराबाद : अभाविप की तेलंगाना सरकार से मांग,

आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के लिए दस प्रतिशत आरक्षण कोटा लागू करे

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आर्थिक कमजोर वर्ग(EWS) कोटे को सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं नौकरियों में बहाल करने की मांग को लेकर तेलंगाना सरकार मंत्री क्वार्टर को घेर लिए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे अभाविप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर – बितर कर दिया। अभाविप के केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य प्रवीण रेड्डी ने कहा कि अगर केन्द्र सरकार गरीब लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के शिक्षा और भेदभाव के दस प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून लाती है और उसे बहाल करती है तो इसे तेलंगाना में क्यों नहीं लागू किया गया है। राज्य सरकार छात्रों के साथ भेदभाव क्यों कर रही है। हमारी मांग है कि बिना किसी देरी के इसे जल्द से जल्द लागू किया जाय। उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार के लापरवाह रवैये के कारण लगभग 60,000 योग्य गरीब छात्र ईडब्लयूएस कोटे का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, यह घोर अन्याय है। अभाविप की यह मांग है टीआरएस सरकार जल्द से जल्द ईडब्ल्यूएस कोटे को बहाल करें। अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम छात्रों की हितों की रक्षा के लिए सड़क पर उतरेंगे।

तेलंगाना की केसीआर सरकार बिना ईडब्ल्यू कोटे को बहाल किये राज्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अधिसूचना जारी कर रहा है जो कि घोर अन्याय है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, स्कूलों, जेईई एडवांस 2020 के नतीजों और सिविल्स (78) के परीक्षा परिणामों ने भी साबित कर दिया कि केंद्र सरकार द्वारा दिये गए 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने गरीब छात्रों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को लाभान्वित किया है।

तेलगांना राज्य के विभिन्न पाठ्यक्रमों में (Ed. CET: 13868, LAWCET: 2830 (3 वर्ष), 789 (5 वर्ष), EAMCET: 65444, B. फार्मेसी: 3280, Pharm D: 535, TSECET: 10418 (Engineering + Engineering) फार्मेसी)) ICET: 22434 (MBA), 1955 (MCA), PECET: 177 (BPEd + DPEd), डिग्री (DOST): 407390, पॉलिटेक्निक: 31012, ITI: 28344, B.Sc. एग्रीकल्चर : 499, टीएस आवासीय कॉलेज: 3000, बसरा IIIT: 1000, CPGET:

32000: टीएस में कुल उपलब्ध सीटें = 626569 × 10% = 62656) 626569 लाख सीटें उपलब्ध हैं और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण से हर साल 62656 छात्रों को लाभ होगा। इसलिए तेलगाना सरकार से हमारी मांग है कि 62 हजार से अधिक छात्रों के भविष्य की चिंता करते हुए अविलंब ईडब्ल्यूएस कोटे को बहाल करें। प्रदर्शन में अभाविप के प्रांत सह मंत्री सुमन शंकर, थोटा श्रीनिवास, भगीरथ, श्रीनिवास, भानु, साईकुमार, विजय और श्रीकांत सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल थे। ■

India's Diplomatic and Strategic tools: POLITICAL WEAPONS IN THE INDIA-CHINA STANDOFF

| Monika Gupta |

Introduction

The past few months have witnessed escalated tensions between India and China at the Line of Actual Control (LAC), with moments of confrontation and negotiation forming the crux of it. China's constant reassertion of force with the purpose of territorial invasion and creating disturbance at the LAC has added to the fueling of political tensions between the two countries and violation of the 1996 agreement on "Confidence Building Measures" that prohibited the use of guns and explosives near the border, necessary for the maintenance of peace.

The situation between the two countries especially became worse when 20 Indian soldiers were martyred in an encounter with the Chinese troops in the Galwan Valley in June 2020 and since then any round of negotiations have failed until recently when the 'five point' agreement has been reached between the Foreign Minister of India, S. Jaishankar and Chinese Foreign Minister, Wang Yi, on the sidelines of the SCO Summit on September 10 in Moscow. At the same time, it's highly doubtful how successful this agreement would be considering the general tendency of China of "fighting and talking simultaneously".

However, there are two things that are significantly coming out of this territorial and military clash between India and China amidst the pandemic. First, China, to a greater extent, has lost its international credibility owing to the Wuhan virus and its international prestige is already at stake and by carrying out attacks at the LAC has further gained international criticisms. Secondly, at the same time, it has been a great opportunity for India to gain the trust of the international community as being a peace loving and

democratic country, which is also seen and constantly reinforced through "negotiating strategies" being employed by India to solve the disputes with China. At the same time, there has been an increased shift in the visible trends of the international community, shifting its interest from China to India as a possible destination of future investments and stronger ties.

India's Upper Hand amidst the India-China conflict

China in the past has also tried its military hacks of intruding within the Indian Territory but has failed significantly owing to the strong and resolute response from the Indian side. The failed intrusions this time are once again a symbol of determined and unwavering India that is strong enough to defend its territorial integrity and sovereignty. Throwing out a clear signal of an indomitable spirit, India has occupied dominant positions across the LAC, including the very recent South Bank of the Pangong Tso (lake) countering Chinese move of occupation at the North Bank of the Pangong Tso. India predominately has increased its presence around the Rezang La and Rechin La which has restricted Chinese movement and has sent clear signals of 'no tolerance' to any threat on its territorial integrity. Also, places such as Spanggur gap, which is geo-strategically very important to China, as this 2 km wide pass was used by China to attack the Indian forces in 1962, is now under the control of the Indian armed forces. Thus, India's constant position of resolving the crisis through negotiations shouldn't be considered its weakness but rather its inherent democratic ideals and adherence to values of peace and prosperity that has defined India globally.

It won't be wrong to associate India's resolute actions at the borders with that of determined leadership in New Delhi. The arbitrary dominance of Chinese influence has well been reverted by the Indian armed forces at the borders and by the government at the Centre through the soft power diplomatic tools. The banning of nearly 200 Chinese mobile apps came as a great shock to China signaling strong disapproval to its disruptive tendencies. It was believed that the data from these apps was being misused by the Communist regime in China. At the same time, PM Modi has sent clear signals of an "AtmaNirbhar Bharat" where he has also encouraged our youngsters to make Indian apps as a replacement to the banned Chinese apps. Thus, we see a clear encounter to China's activities at the LAC which has proved harmful for the political regime of China adding to the strained bilateral relations.

Amidst the strained relations with

China, India has been successful to an extent of building international pressure on China especially from global powers like the United States, United Kingdom etc. Some European countries too have acted strongly against China, citing it as the reason for bringing in catastrophe to the world. Thus, we see, China is already on a weaker side in terms of losing its international credibility and trust. This can be a good opportunity for India in terms of garnering international support that might prove helpful in case of an armed conflict between India and China. Also, this might prove effective in terms of exercising diplomatic pressure on China's weak points like the South China Sea, Taiwan, Hong Kong etc. Thus, we see, India has varied options in front of it to encounter any moves by China on the LAC, it's the Chinese side which needs to rethink and rebuild on its lost international prestige and bilateral and global relations.

Use of India's Diplomatic Cards

It is beyond doubt that diplomacy through the usage of soft power tools has been well played off by the Modi led government since their first term in 2014. An equally opposite has been the case of Chinese President Xi Jinping where he has tried since 2013 to exert dominance and power through his aggressive policies especially in the Asian continent, with an intention of controlling and ruling in its neighborhood. The cause of the current pandemic has been very much allegedly accredited to China's usage of Wuhan virus, as a biological tool of controlling and influencing the world, which however, has proved futile and detrimental to its own global image. Not only this, China has been aggressively involved in unilaterally deciding on action plans with the countries in the South East Asia. But, one front, where China is finding difficult to handle the situation is from India, where since 2017, it has been trying excursions and other military and non-military tactics but has failed consistently.

This has been hugely possible because of India's diplomatic strategies under the leadership of PM Modi. The government has ensured that India's sovereignty and integrity is the government's and nation's priority and any measures against this will be dealt accordingly. For instance, this is well reflected in the United Nations Security Council (UNSC) when the Kashmir issue wasn't moved in the United Nations (indirectly considering it as India's prerogative), when China tried to raise it on behalf of its all-weather friend Pakistan. Thus, soft power diplomatic strategies have always worked in favor of India and it has been evidently viable in the case of India-China relations.

Conclusion

India, especially after 2014, has tried its best to have a peaceful neighbourhood but at the same time, it has also reiterated the idea of a unified India and any attempt at forging it shall be met with strong resistance. This is exactly what is being witnessed in the India-China conflict. Considering the situation, India is left with three options, first to declare a full-fledged armed conflict, second to occupy territories under the Chinese control as a tool of retaliation and third, through constant negotiations and soft power tools. India is potentially capable of resorting to any or all of the techniques but it largely depends on the responses from the Chinese side. India, being a peace loving nation has been trying its best, to politically and diplomatically solve the conflict but as the saying goes, 'the things on the ground will eventually decide the things on the negotiating table' and India seems determined to adhere to it. ■

परिषद की पाठशाला

RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 NOVEMBER, 2020
DATE OF PUBLISHING: 8 NOVEMBER, 2020
POSTAL REGD. NO.: DL(C)-11/1409/2020-2022
POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI

JOIN ABVP

Register at
WWW.ABVP.ORG
and be a part of
World's Largest
Student Organisation!

IGNITING MINDS, REBUILDING BHARAT

@ABVPVoice